THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) and (b) Several NRI organisations have in the past represented for permission to invest in real estate, housing development, plantation and other agricultural activities and also in the waste land development. Under the existing policy NRI's are permitted to purchase one residential property freely, but are not permitted to invest in real estate etc. Existing schemes, rules and regulations regarding NRI investments are continuously under review and suitable changes are made where necessary.

Remittances to India by the Indian Living Abroad

3471. SRI SUNIL BASU RAY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indians living abroad are facing distinct disadvantages in remitting money to India;

(b) whether Government's attention has been drawn to the letter published in 'The Statesman' Delhi edition dated the 15th August, 1990 in this regard; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) to (c) A letter to the Newspaper about difficulties in remittances faced by NRIs has come to our notice. Government is not aware of such problems being generally faced by NRIs. However, RBI has been advised to take appropriate action wherever considered necessary.

खाद और बीज की खरीद के लिए किसानों को केन्द्रीय सहायता

3472. **डा. अबरार अहमद खान** वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष वर्षा शुरू होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक और बीज की खरीद के लिए ऋण देने हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ख) राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान अब तक बांटे गए नए कृषि ऋणों का ब्यौरा क्या है तथा दस हजार रुपये तक के ऋण माफ किए जाने की घोषणा के अनुसार कितने किसानों के पुराने ऋण माफ किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री : (क) और (ख) विभिन्न फसलों को उगाने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले बैंक वित्त की मात्रा जिला स्तर पर बनाए गए तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है जो खाद एवं बीज, मिट्टी की प्रकृति, जल की उपलब्धता, किसानों की खपत, आवश्यकता, मजदूरी इत्यादि सहित विभिन्न निविष्टियों के प्रचलित लागत को ध्यान में रखकर उसका निर्धारण करती है। खाद की उपलब्धता और वितरण संबंधी व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और बैंकिंग क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए वित्तपोषण करता है।

राजस्थान के सहकारी बैंकों ने चालू वर्ष के जून 1990 तक की अवधि के लिए 13.08 करोड़ रुपए तक के नये कृषि ऋण दिए हैं। ऋण राहत योजना के अन्तर्गत किसानों के पहचान की प्रक्रिया जारी है और इस ऋण राहत योजना से लाभान्वित होने वाले उधारकर्ताओं की कार्रवाई पूरी होने के पश्चात् नये ऋण दिए जायेंगे।

Creation/Upgradation of Posts in Secretariat Offices

3473. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that instructions have been issued by his Ministry to the effect that the approval of the Cabinet is required to be taken for creation/upgradation of posts in Secretariat Offices after providing matching savings in equal proportions;

(b) whether it is also a fact that for the purpose of determination of matching